S. No.	Station/City	No. of Dwelling Units completed/ under constn.	Completed/To be completed during the year
Completed			
1.	Chennai	524	1995
2.	Nerul, Navi Mumbai	384	1996
3.	Punchkula	98	1997
4.	Noida Phase-I	692	1997
5.	Calcutta	576	1998
6.	Noida Phase-II	508	1998
7.	Kharghar, Navi Mumbai	1230	1998
8.	Gurgaon Phase-I	1088	1999
Under Construction			
1.	Chandigarh	305	1999
2.	Bangalore	603	2000
3.	Ahmedabad	336	2000
4.	Kochi	104	2000
5.	Hyderabad	360	2000
6.	Gurgaon Phase-II	852	2000

(c) and (d) No, in the light of reply at (a) and (b) above.

Rehabilitation Policy for Jhuggi Dwellers

3083. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have since finalised rehabilitation policy for 6000 jhuggi dwellers who are likely to be shifted on account of implementation of Delhi Metro Project;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) to (c) The Rehabilitation Policy in respect of Project affected presons due to Delhi MRTS Project is under active consideration by the Government of Delhi.

गोल मार्किट फ्लैट के एम एस फ्लैटों के निवासियों को बेहतर सुविधाएं

3084. श्री मुनव्वर हसन: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पेशवा रोड, गोल मार्किट, नई दिल्ली स्थित एम एस फ्लैटों के ए और बी ब्लाकों के निवासियों को रोजमर्रा की शिकायतों की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सिविल विंग द्वारा अनदेखी की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मानदंडों में वर्णित सुविधाएं उक्त फ्लैटों में उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकारी क्वार्टरों में मुहैया कराई गई सुविधाओं के मानदण्ड समय-समय पर संशोधित

किए गए है। निर्माण के समय लागू मानदण्डों का स क्वार्टरों में पालन किया गया है। पेशवा रोड फ्लैटों के मामले में भी ऐसा किया गया किंतु संशोधित मानदंड में उपलब्ध संविधित सुविधाएं आबंटियों को पूरी तरह मुहैया नहीं कराई जा सकीं।

(घ) ऐसे क्वार्टरों में आबंटियों के अनुरोध पर आवंटी द्वारा कार्य की अनुमानित लागत के आंशिक भुगतान पर मानदंडों के अनुसार सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

सरकारी क्वार्टरों में रह रहे अनधिकृत लोग

3085. **श्री मुनव्वर हसनः क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने 1998 में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को गोल डाकखाना, नई दिल्ली के "जी" प्वाइंट में, जिसमें पहले डाक और तार विभाग के मकान थे, जमीन आवंटित की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त क्वार्टरों में अनधिकृत व्यक्ति रह रहे हैं और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कपटपूर्ण सहयोग से मुफ्त बिजली और पानी भी प्रयोग में ला रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी; और

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद उक्त जमीन/क्वार्टरों को कब तक अपने कब्जे में लेगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां। इस मंत्रालय ने वर्ष 1996 में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को "जी" प्वाइंट नई दिल्ली में भूमि आबंटित की थी।

(ख) से (घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

Urban Housing in Assam

3086. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of projects/schemes undertaken by Government for development of urban housing in Assam during the preceding three years;

(b) the details of grants allocated for each of these schemes/projects;

(c) the details of achievement levels; and

(d) what are the upcoming projects/ schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) to (d) Housing being a State subject, the State Governments are to formulate and implement housing schemes as per their priorities and requirements. Central Government does not undertake any project/scheme for development of urban housing in the States.

However, the Housing & Urban Development Corporation (HUDCO) has provided loan assistance to the State Government for undertaking various housing schemes. Details for the last three year are as given below:

(Rs. in crores)

Year	No. of Scheme	Project cost	Loan Amount	Dwelling units
1996-97	6	41.17	21.04	515
1997-98	5	28.14	16.23	1424
1998-99	9	265.04	172.53	37207

Besides the above, HUDCO has received 16 schemes seeking loan assistance of Rs. 20.92 crores. These are at various stages of sanction.